

# पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण में 15 से 20 अंक बढ़े तो नपेंगे शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में शिक्षा बोर्ड सख्त

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाने जा रहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी छात्र के अंकों में 15 से 20 अंकों की बढ़ोतरी पाई जाती है, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड का यह फैसला पिछले कुछ वर्षों में पुनर्मूल्यांकन के लिए आने वाले आवेदनों की बाढ़ को देखते हुए लिया गया है। बड़ी संख्या में आवेदन न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि इससे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठती हैं। अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अंकों का अंतर आना शिक्षकों की घोर लापरवाही को दर्शाता है।

देखा गया है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्रों के अंक 50 से सीधे 85 तक पहुंच जाते हैं। इससे न केवल मूल परिणाम की विश्वसनीयता कम होती है, बल्कि राज्य की मेरिट सूची भी प्रभावित होती है। बोर्ड ने सभी मूल्यांकनकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे उत्तरपुस्तिकाओं की जांच पूरी ईमानदारी और सतर्कता के साथ करें ताकि छात्रों को उनके परिश्रम का सही फल मिल सके और बेवजह के विवादों से बचा जा सके। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में इस बार पारदर्शिता लाई जा रही है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अंकों

5,000

से अधिक कर रहे हैं मूल्यांकन



धर्मशाला। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ एवं व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही हैं। डॉ. शर्मा ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा एवं गोपनीयता के साथ करने के लिए कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन प्रक्रिया अत्याधुनिक सर्विलांस प्रणाली के अंतर्गत संचालित हो रही है, जिससे प्रत्येक गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कार्य 41 केंद्रों पर चल रहा है, जहां पर 10वीं और 12वीं कक्षा की 11 विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पांच हजार से अधिक शिक्षक कर रहे हैं। ब्यूरो

का निर्धारण करें। अगर पुनर्मूल्यांकन के दौरान 15 से 20 अंक बढ़ते हैं, तो मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो

# पुनर्मूल्यांकन में 15 से 20 अंक बढ़े तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई

**संवाद सहयोगी, जागरण •**  
**धर्मशाला :** हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

बोर्ड ने निर्णय लिया है कि यदि पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी विद्यार्थी के 15 से 20 अंकों की वृद्धि होती है तो संबंधित शिक्षक की जवाबदेही तय की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले तीन वर्षों में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए

बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

सभी मूल्यांकनकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे उत्तरपुस्तिकाओं का निष्पक्ष और ईमानदारी से मूल्यांकन करें, ताकि छात्रों को सही अंक मिल सकें और विवाद की स्थिति से बचा जा सके। कई बार पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के बाद विद्यार्थियों के अंक 50 से 85 तक बढ़ जाते हैं, जो चिंता का विषय है।

अंक वृद्धि से मेरिट पर भी असर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर होता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षकों को निष्पक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

## मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर एक्शन मोड में स्कूल शिक्षा बोर्ड

# पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण में 15-20 अंक बढ़ें तो पेपर चेक करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई

### अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पारदर्शिता पर फोकस कर रहा है, इसी कड़ी में मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बोर्ड एक्शन मोड में है। पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी विद्यार्थी के अंकों में 15 से 20 अंकों की वृद्धि होती है तो संबंधित शिक्षक यानी पेपर चेक करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही शिक्षक पर कार्रवाई भी होगी।

गौरतलब है कि पिछले तीन साल में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में बोर्ड ने भी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाने का ऐलान कर चुके बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि पुनर्मूल्यांकन

या पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी छात्र के अंकों में 15 से 20 अंकों तक की बढ़ोतरी होती है, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए आने वाले आवेदनों की बढ़ रही संख्या के चलते बोर्ड ने यह फैसला लिया है। लगातार बढ़ रही यह संख्या मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है।

इसे गंभीरता से लेते हुए इस बार मूल्यांकन कार्य में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड प्रशासन ने सभी मूल्यांकनकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे उत्तरपुस्तिकाओं का निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करें, ताकि छात्रों को उनके सही अंक मिल सकें। विद्यार्थी जब पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं तो कई बार उनके अंक 50 से 85 हो जाते हैं, जोकि एक चिंता का विषय है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के बाद अंकों के

उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में इस बार पारदर्शिता लाई जा रही है।

मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन कार्य करें और ईमानदारी के



साथ प्रश्नों के उत्तरों के अंक विद्यार्थियों को दें। अगर पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के 15 से 20 अंक बढ़ते हैं, तो मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि भविष्य में शिक्षक पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन कार्य को अंजाम दें।

**-डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष,  
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड**

बढ़ने से मेरिट भी प्रभावित होती है, जिसका असर विद्यार्थियों पर पड़ता है।

इंतजार

शिक्षकों का परीक्षा परिणाम तैयार करने में जुटा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

# 15 अप्रैल के बाद सीबीएसई स्कूलों को मिलेंगे टीचर

सवेरा न्यूज़/यशपाल सिंह

धर्मशाला, 5 अप्रैल : हिमाचल

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षा

स्तर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य

से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

के तहत कई सरकारी स्कूलों

को सीबीएसई बोर्ड के अधीन

लाया गया है, लेकिन शिक्षकों

की नियुक्ति नहीं हो पाई है

हालांकि नए शैक्षणिक सत्र की

शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि



सीबीएसई स्कूलों के लिए चयनित

किए जाने वाले शिक्षकों का

परीक्षा परिणाम अभी तक

घोषित नहीं हुआ है।

जानकारी के अनुसार,

प्रदेश सरकार ने

हिमाचल प्रदेश स्कूल

शिक्षा बोर्ड से जुड़े कुछ

स्कूलों को सीबीएसई

बोर्ड के तहत संचालित

करने का निर्णय लिया है। इस योजना के

अंतर्गत प्रदेशभर में करीब 158 स्कूलों को

सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जाना है। इन

स्कूलों में तैनात किए जाने वाले शिक्षकों के

चयन के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा

बोर्ड द्वारा एक विशेष परीक्षा आयोजित की

गई थी। इस परीक्षा को पास करने वाले

शिक्षकों को ही इन स्कूलों में नियुक्त किया

जाना है। हालांकि, परीक्षा संपन्न हुए काफी

समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इसका

परिणाम घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों के

मुताबिक, इस परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल

के बाद जारी होने की संभावना है। वहीं,

शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि

परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परिणाम

तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। इसे

जल्द ही अंतिम रूप देकर प्रदेश सरकार को

सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा

परिणाम घोषित किया जाएगा और शिक्षकों

की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब

सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार

परीक्षा परिणाम कब तक घोषित करती है

और कब तक इन स्कूलों में शिक्षकों की

सीबीएसई स्कूल

में तैनाती पाने

वाले टीचरों के लिए

एक परीक्षा आयोजित

की गई है। परीक्षा

परिणाम को तैयार किया

जा रहा है, उम्मीद है 15

अप्रैल तक परिणाम तैयार कर शिक्षा विभाग को

सौंप दिया जाएगा। (डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष)

नियुक्ति पूरी होती है, ताकि छात्रों की पढ़ाई

सुचारू रूप से चल सके।



डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष

